

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

दिनांक 20/24-16-18  
/2016 पुनरीक्षण

तेजसिंह पुत्र स्व० श्री अमरसिंह  
निवासी-ग्राम मुगालिया छाप, तहसील  
हुजूर जिला भोपाल, म०प्र०

--आवेदक

बनाम

गिरधारीलाल पाटीदार पुत्र श्री भंवर  
जी पाटीदार निवासी-ग्राम मुगालिया  
छाप, तहसील हुजूर जिला भोपाल,  
म०प्र० --अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता  
1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 06/06/2016 पारित  
द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल  
प्रकरण क्रमांक 245/2015-16/बी-121 व उनवान  
तेजसिंह बनाम गिरधारीलाल, जिसके द्वारा आवेदक के  
पक्ष में पारित स्थगन आदेश दिनांकी 03/06/2016  
निरस्त किया गया।

24/6/16  
24/6/16  
24/6/16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.2024-पीबीआर/2016

जिला भोपाल

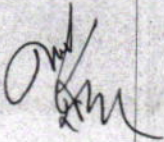
स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

15-09-2016

आवेदक की ओर श्री एस0के0श्रीवास्तव, अधिवक्ता तथा अनावेदक की ओर से श्री अनिल गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-6-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदक को पूर्व में दिये स्थगन को निरस्त किया गया है । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24-6-16 को इस आदेश के विरुद्ध निगरानी ग्राह्य करते हुये तहसीलदार के वादग्रस्त आदेश दिनांक 6-6-16 का कियान्वयन स्थगित किया गया । तथा बाद में दूसरे पक्ष के उपस्थित होने पर उभयपक्ष को सुनने के बाद दिनांक 5-7-16 को अंतरिम आदेश पारित कर दिनांक 24-6-16 के स्थगन आदेश को निरस्त किया गया । इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-7-16 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष को यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अब इस न्यायालय में मात्र स्थगन के बिन्दु पर प्रचलित निगरानी को आगे सुने जाने का कोई औचित्य न होने से यह प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन में कार्यवाही करें । इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।



  
अध्यक्ष